भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1183
उत्तर देने की तारीख : 23 मार्च, 2012

केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों हेतु नयी गणवेश

1183. श्री बलवंत उर्फ बाल आपटेः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों की गणवेश बदलकर नई डिजाइनर लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो डिजाइनर कंपनी को किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बाजारी ताकतों के दबाव में यह कदम उठा रही है;

(घ) क्या इससे अभिभावकों पर पड़ने वाले बोझ के बारे में सरकार ने कोई आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो इससे कितना खर्च बढ़ने की संभावना है;

(च) क्या सरकार बालिकाओं को यह गणवेश निःशुल्क देने का विचार रखती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डा. डी. पुरंदेश्वरी)

(क) और (ख): जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने स्कूल यूनिफार्म को पुनः डिजाइन करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। तदनुसार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने स्कूल यूनिफार्म को पुनः डिजाइन करने हेतु राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), नई दिल्ली, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को एक परियोजना सौंपी है। परियोजना लागत 18,41,176 रुपए (केवल अठारह लाख, इकतालीस हजार, एक सौ छिअत्तर रुपए) है।

(ग): जी, नहीं।

(घ) और (ड.): राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान से स्कूल यूनिफार्म को डिजाइन करते समय लागत कारक सहित विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है।

(च): जी, नहीं।

(छ): प्रश्न नहीं उठता।

*****